

मुख्यमंत्री ने पचपदरा में प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की जनसभा में पानी, बैठने तथा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए

बालोतरा/जयपुर, 13 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बालोतरा में पचपदरा की एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बालोतरा में प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को देश के पहले एचपीसीएल इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ बालोतरा में करेंगे। इस रिफाइनरी के माध्यम से देश-प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही, यह रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी।

इस दौरान शर्मा ने रिफाइनरी की क्लूड डिजिटेशन यूनिट, रिफाइनरी में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफाइनरी प्रतिनिधियों से संवाद कर उनका अनुभव भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जनसभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल के ले आउट का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा के विशेष

इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी का निरीक्षण कर आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की

बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए जनसभा में आमजन के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग आपस में

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफायनरी की क्लूड डिजिटेशन यूनिट, रिफायनरी में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफायनरी के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली।

समन्वय कर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर सजावट में राजस्थान की कला संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे आगन्तुक प्रदेश की ऐतिहासिक गौरवशाली परम्परा से रूबरू हो सकें। इससे पहले हैलिपेड पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्री जोराम कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री केके बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कई अन्य नेता, मंत्री व अफसर मौजूद थे।

गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया तो उम्र कैद व 25 लाख रूपए तक जुर्माना

पंजाब विधानसभा में सर्व सम्मति से बेअदबी कानून पारित

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अब कोई पत्थर दिला ही होगा, जो ऐसा करने के बारे में सोचेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो पीढ़ियों तक उसका अहसास रहेगा।

चंडीगढ़, 13 अप्रैल। पंजाब में करीब एक दशक से चुनावी मुद्दा बने बेअदबी के मामलों में अब कड़ी सजा देने के लिए सोमवार को बेअदबी कानून पारित किया गया है। बैसाखी के अवसर पर पंजाब विधानसभा के विशेष एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 सर्वसम्मति से पास किया गया। इस विधेयक में आरोपितों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में यह विधेयक पेश किया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक अभी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। गैर सिखों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि) के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सीएम ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों से भी राय लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा।

इस विधेयक को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और स्पीकर कुलतार सिंह संघर्ष के बीच बहस हुई। बाजवा ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इस मामले में

बनाई गई निजजर कमेटी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए।

इससे पहले अप्रैल, 2025 में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को शामिल किया गया था, लेकिन उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। वर्तमान पारित विधेयक केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर केंद्रित है। सत्र के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर सख्त सजा रखने संबंधी बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब कोई पत्थर दिला ही होगा, जो इस घटना के बारे में सोचेगा। अगर सोचेगा तो उसे पीढ़ियों तक उसका अहसास रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेलेक्ट कमेटी का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया है,

क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी। ऐसे में सभी धर्मों के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। अभी सभी से राय लेनी होगी। कमेटी अब सभी धार्मिक लोगों के पास जाकर राय लेगी।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) देते हुए, न्यायमूर्ति ने कहा, “आप जिस देश में पैदा हुए हैं, वहां मतदान का अधिकार केवल संवैधानिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। यह ऐसा है, जैसे आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं और सरकार चुनने में मदद कर रहे हैं।”

जब नायडू ने कहा कि पश्चिम बंगाल किसी भी दृष्टिकोण से एसआईआर वाले राज्यों की तुलना में अलग नहीं है, तो न्यायमूर्ति वागची ने कहा कि बिहार में तार्किक असंगति सूची नहीं थी।

नायडू ने कहा कि बिहार में भी अस्वीकृतियां हुईं, लेकिन कोई अपील प्रक्रिया नहीं थी।

इस पर न्यायमूर्ति वागची ने कहा, “अपील न्यायाधिकरण के लिए यह मतदाता सूचियों को बढ़ाने या घटाने का मुकाबला नहीं है। उन्हें समावेशन के सिद्धांतों पर सुनवाई करनी होगी।”

‘तृणमूल अलगाववादियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अलगाववादियों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए दोषी ठहराया।

देश की सुरक्षा के प्रति टीएमसी की “अविकेकपूर्ण नीति” का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा: “हमारा सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि भारत माता की भुजा है। लेकिन दोस्तों, आंखों को खोलना चाहिए कि तृणमूल ने वोट बैंक को खूब करने के लिए क्या-क्या किया?”

उन्होंने आगे कहा, “देश में एक टुकड़े-टुकड़े गैंग (अलगाववादी) है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी।

उन्होंने उत्तर-पूर्व को देश से अलग करने की बातों की थी। ऐसे लोगों को तृणमूल ने सड़क से संसद तक समर्थन दिया।”

सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अनौपचारिक रूप से चिकन नेक कहा

जाता है, मुख्य भारत को उत्तर-पूर्व से जोड़ता है। यह रास्ता अपने सबसे संकीर्ण हिस्से पर लगभग 20-22 किमी चौड़ा है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा के करीब स्थित है।

बंगाल के मंत्री और तृणमूल उम्मीदवार ब्रज्य बसु ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “वे हर उस व्यक्ति को टुकड़े-टुकड़े गैंग कहते हैं जो भाजपा के खिलाफ है।”

कांग्रेस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र के तहत हो रही इस तीन दिवसीय बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से संबंधित संशोधन एवं परिशीलन से जुड़े विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है।

15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन होगा

पटना, 13 अप्रैल। बिहार में नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार दोपहर 2 बजे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक दल की बैठक अपने आवास पर बुलाई है।

वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3:30 बजे अपने विधायकों की बैठक तय की है, जिसमें केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक दल के नेता, यानी राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। दोनों दलों की बैठकों के बाद शाम 4 बजे विधानमंडल के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता को गठबंधन का नेता चुना जाएगा।

नीतीश 14 अप्रैल को राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे।

भाजपा और जदयू सूत्रों के अनुसार, बिहार में करीब पांच माह के भीतर नई सरकार का गठन 15 अप्रैल को किया जाएगा और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की संभावना है। इधर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर सोमवार को राजग नेताओं की अहम बैठक हुई। जदयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह ने उनसे मुलाकात की, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी भी वहां पहुंचे। फिलहाल सरकार गठन की गतिविधियों का केन्द्र नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के आवास बने हुए है।

अमेरिका ने जहाजों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कुछ संकेत हैं कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों पर लागू होगी। अमेरिकी नौसेना ने पहले ही संदेश भेज दिए हैं कि कोई भी ईरानी जहाज, जो खाड़ी के माध्यम से या होर्मुज की ओर बढ़ रहा है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रहा है और इन्हें निष्क्रिय किया जा रहा है। यह मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच संघर्ष विराम को खतरे में डाल सकता है और वे एक-दूसरे पर हमले शुरू कर सकते हैं। ईरान अपनी ओर से अन्य प्रकार के हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा

है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद पेझेशकियन ने व्लादीमिर पुतिन से संपर्क किया है, ताकि विवादों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सके।

होर्मुज नाकेबंदी ईरान के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान अपने कच्चे तेल को होर्मुज के मार्ग से ही भेजता रहा है। इसके अलावा, हिंसा के फैलने के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने ईरान को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद की, जिससे उसने अपनी कार्रवाहियों को वित्तपोषित किया।

बंगाल में एक्शन मोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) राजनीतिक दिग्गजों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोर्पोरेट संस्थाओं को निशाना बनाया, और हवाला लेने देन और “अपराध की आय” का एक व्यापक नेटवर्क उजागर किया।

एजेंसी की नजर उच्च पदस्थ अधिकारियों पर कड़ी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी ने कई घोटालों में कथित रूप से शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैडिकल पती घोटाले के अन्तर्गत, संतनु सिन्हा बिस्वास, पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा, कोलकाता), अपने बेटे

को कथित रूप से निजी मैडिकल कॉलेज में घोखाघड़ीपूर्ण एनआरआई के तहत प्रवेश दिलाने के आरोप में जांच के घेरे में है। समन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने के बावजूद, ईडी ने उनकी उपस्थिति के लिए नए आदेश जारी किए हैं, यह कहते हुए कि जांच पर कोई रोक नहीं है।

‘सरकार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है। विशेषकर दक्षिण भारत की पार्टियां, जिन्हें लगता है कि वे हाशिप पर आ जाएंगी, और छोटे राज्यों को, जिन्हें लगता है कि वे राष्ट्र शासन में अप्रासंगिक हो जाएंगे, परिसीमन के कारण इस विधेयक के कड़े रूप से शांति

मॉनसून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 को लेकर शुरुआती पूर्वानुमान जारी किया है। इस बार देश में मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल वर्षा लगभग 92 प्रतिशत लॉन्ग परियर्ड एवरेज (यानी किसी क्षेत्र में

मौसम विभाग की शुरुआती रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ें।

एक निश्चित अवधि में 30 या 50 वर्षों की दर्ज की गई औसत वर्षा) रहने का अनुमान है, जिसमें 5 प्रतिशत की संभावित त्रुटि हो सकती है। देश के लिए

एलपीए (1971-2020 के आधार पर) 87 सेंटीमीटर तय है।

आईएमडी ने सोमवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि फिलहाल प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना जैसी स्थिति बनी हुई है, जो धीरे-धीरे इंफ्लूएन्स न्यूट्रल की ओर बढ़ रही है। हालांकि, मानसून सीजन के दौरान एल नीनो बनने की संभावना जताई गई है।

आशा भोंसले पंचतत्व में विलीन हुईं, बेटे ने मुखार्गि दी

महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गाई ऑफ ऑनर दिया

मुंबई, 13 अप्रैल। भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोंसले सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। 92 वर्ष की आयु में रविवार को मुंबई के ब्रीच कैन्डी अस्पताल में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया था। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है।

सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लोअर परेड स्थित उनके निवास कासा ग्रांटे में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया।

इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा दादर स्थित शिवाजी पार्क के लिए रवाना हुई। करीब पांच किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर हजारों प्रशंसकों का हजूम उमड़ पड़ा। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने अपनी प्रिय ‘आशा ताई’ को फूलों की वर्षा कर भावभीनी विदाई दी।

आशा भोंसले का पार्थिव शरीर फूलों से सजी गाड़ी में शिवाजी पार्क ले

सफेद और पीले फूलों से सजी गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया गया जहां उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

जाया गया। गाड़ी को उनके पसंदीदा सफेद और पीले फूलों से सजाया गया था। उस पर उनकी एक बड़ी तस्वीर लगी थी।

जैसे ही उनका पार्थिव शरीर वाहन में रखा गया, पुलिस बैंड ने शोक धुन बजाकर उन्हें सम्मान दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम यात्रा शिवाजी पार्क पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

‘महामानव ‘नीतीश’ के बिना बिहार अधूरा है’

पटना, 13 अप्रैल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को संभवतः अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हम के संस्थापक एवं केन्द्रीय मंत्री जीवन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से पहले

केन्द्रीय मंत्री और ‘हम’ पार्टी के संस्थापक जीवन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश के सी.एम पद से इस्तीफा देने से पहले भावुक ‘पोस्ट’ डाला।

भावुक पोस्ट कर अपनी भावनाएं साझा की है। नीतीश कुमार को महामानव बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनके बिना बिहार अधूरा रहेगा।

अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सोमवार को उन्होंने कहा कि नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। सबको पता है कि आपका यह ख़ाब था कि आप देश के चारों सड़कों के सदस्य रहें, पर आपके इस ख़ाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है।

टोंक, 13 अप्रैल। पूर्व उपमुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सोमवार को टोंक पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में माला पहनाकर और साफा बंधवाकर कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि गांवों, शहरों और यूनिवर्सिटी में भी चुनाव कराए जाने चाहिए, वर्तमान में प्रशासक और अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं।

भाजपा सरकार के आने के बाद से पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालयों के चुनाव नहीं कराए गए हैं, जबकि यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, जो संविधान में भी अंकित है। पायलट ने कहा कि विपक्षी विधायकों तथा सांसदों के वजेट में भेदभाव होता है, लेकिन हम जनता के काम करवाएंगे। उन्होंने बताया कि टोंक के लिये मैडिकल कॉलेज, पुल और नर्सिंग कॉलेज जैसे कई प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें अपेक्षित स्तर पर औपचारिक शुरुआत नहीं मिल पाई। कानूनी रूप से भी सरकार पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन न तो निर्वाचन आयोग और न ही सरकार इस दिशा में गंभीर दिख रही है। कोर्ट ने 15



पूर्व उपमुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को टोंक के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा दी थी, इसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा पाई। लगाएने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, क्योंकि उसे डर है कि परिणाम उसके पक्ष में नहीं

पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं

उन्होंने कहा कि सरकार को हार का डर है इसलिए वह गांवों व शहरों के चुनाव टाल रही है

काँग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि टोंक में मैडिकल कॉलेज, पुल और नर्सिंग कॉलेज जैसे कई प्रोजेक्ट बनाये गए हैं, पर इन्हें अपेक्षित स्तर पर औपचारिक शुरुआत नहीं मिल पाई है।

आई है। देशभर में मनरेगा की स्थिति कमजोर होती जा रही है, जो चिंता का विषय है।

इससे पहले सर्किट हाउस में सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं, तथा उन्होंने गत दिनों हुए पथराव को लेकर पूरा घटनाक्रम पायलट को बताया। पायलट ने कहा कि क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए कमजोर किया जा रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सरदार लाखां लोगों को इस योजना से रोजगार मिलता था, लेकिन अब ग्रामीण विकास के कार्यों में गिरावट